संपादकीय

छंटनी के इन दिनों में कर्मचारियों को सलाह

भारत में सरकार के दावे चाहे जो हों चारों तरफ से छंटनी की खबरें आ रही हैं। कुछ तो अमरीका की वजह से आईटी से जुड़ी नौकरियां वहां भी कम हो रही हैं, और उसके असर से हिन्दुस्तान में भी कम हो रही हैं, लेकिन वही अकेली जगह नहीं हैं। आज खबर आई है कि टाटा मोटर्स मैनेजमेंट के स्तर पर पंद्रह सौ लोगों की छंटनी कर रहा है। और यह छंटनी मजदूरों की नहीं है, मैनेजरों की है। इससे परे भी बहुत सी छोटी और मझली कंपनियों और दूसरे तरह के कारोबार में लगातार नौकरियां घट रही हैं, बढ़ तो कहीं नहीं रहीं। ऐसे में सभी कामगारों को अपने काम को बचाने की फिक्र करनी चाहिए।

दरअसल किसी भी संस्थान में जब किसी को नौकरी से हटाने की बात आती है, तो जो सबसे निकम्मे कर्मचारी रहते हैं, उनकी बारी सबसे पहले आती है। इसलिए सारे कामगारों को इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर नौकरी उनके लिए मायने रखती है, तो उनको मेहनत और ईमानदारी से मैनेजमेंट के सामने अपनी ऐसी साख बनाए रखना चाहिए कि उनकी नौकरी जाने की बारी सबसे आखिर में आए। अब अगर किसी कंपनी ने उत्पादन ही घट जाए, कारोबार ठंडा हो जाए, तो एक अलग बात है, लेकिन ऐसा न होने पर काबिल लोगों को निकालने के बारे में कोई मैनेजमेंट नहीं सोचता है। नौकरी के साथ, और खासकर भारत जैसे देश में जहां पर लोग रातों-रात हटाए नहीं जा सकते, वहां पर कर्मचारियों की सोच नौकरी के हमेशा जारी रहने की हो जाती है। और ऐसा होता नहीं है। देश के मजदूर कानून बहुत मजबूत नहीं है, तो कमजोर भी नहीं है। लेकिन कानूनों पर अमल इतना कमजोर है कि मैनेजमेंट लोगों को आसानी से निकाल देता है, और बरसों तक कर्मचारी अपना बकाया भी वसूल नहीं कर पाते, मुआवजा तो दूर की बात है।

नौकरी लंबी होने से और उसकी निश्चिंतता होने से एक दिक्कत यह होती है कि कर्मचारी अपने काम को बेहतर बनाने को भूल ही जाते हैं। आज किसी भी कामकाज में टेक्नालॉजी का दखल इतना बढ़ रहा है, और लगातार बदल रहा है, कि जो लोग नई मशीनों पर, नए कम्प्यूटरों पर काम करना नहीं सीख पाते, उन्हें मैनेजमेंट अपनी छाती पर बोझ मानकर चलता है। यह सिलसिला बहुत लंबा नहीं चल पाता और ऐसे लोग जो कि वक्त के साथ कदम मिलाकर नहीं चल पाते हैं, वे नौकरी खो बैठने का खतरा पाले रखते हैं। आज दुनिया में तेल का भाव जमीन पर है, इसलिए बाकी बहुत से कारोबार अभी भी ऊंचाई पर हैं। अगर पेट्रोलियम महंगा होगा, तो भारत की अर्थव्यवस्था चौपट हो जाएगी, और ऐसे बुरे वक्त के लिए लोगों को तैयार रहना चाहिए, नौकरी देने वालों को भी, और नौकरी पाने वालों को भी। बुरे वक्त में अच्छे-अच्छे मालिक का हौसला जवाब दे जाता है, और कर्मचारियों को कहीं भी काम नहीं मिल पाता। इसलिए हर किसी को अपने काम को बेहतर बनाकर अपनी नौकरी की गारंटी बनाकर रखना चाहिए।

परेश रावल की बात मामूली बात नहीं

■ अपूर्वानंद

अरुंधति रॉय को सेना की गाड़ी के आगे बाँध देना चाहिए बजाय पत्थर चलाने वालों के। क्या परेश रावल ने गुस्से में यह वाक्य कह दिया?

लेकिन गुस्सा किस चीज पर? क्या कल या परसों अरुंधति रॉय ने कुछ कह दिया है जिसे परेश रावल बर्दाश्त न कर सके? दरअसल, पाकिस्तानी मीडिया ने बताया कि अरुंधति रॉय ने हाल में श्रीनगर में एक जगह यह कहा है कि सेना की तादाद सात लाख से बढ़ाकर सत्तर लाख करके भी भारत घाटी में अपना मकसद पूरा नहीं कर सकता। लेकिन वे एक अरसे से वहाँ गई भी नहीं हैं, यह उनके करीबी बताते हैं। फिर भी यह खबर काफी थी कि परेश रावल के क्रोध का बाँध टूट जाए।

परेश रावल एक अभिनेता हैं और नाटकीय ढंग से उन्होंने क्रोध व्यक्त किया। वे चाहें तो कह सकते हैं कि यह सिर्फ रूपक था, अरुंधति रॉय का अर्थ व्यक्ति अरुंधति नहीं, हरेक मानवाधिकार कार्यकर्ता है, या वह जो कश्मीर में भारतीय सेना की कार्रवाई की किसी भी तरह आलोचना करता है।

लेकिन रावल की बात में कुछ और दिक्कतें हैं। मसलन, महीने भर पहले कश्मीर में मेजर गोगोई ने जिस शख्स को अपनी जीप के आगे बाँध कर कई किलोमीटर घुमाया, वह पत्थर चलाने वालों में न था।

फारूक अहमद डार के साथ जो सलूक सेना ने किया उससे यही साबित हुआ कि भारत कश्मीरियों में फर्क नहीं करता और कश्मीरी होना भर भारतीय सेना की नजर में एक तरह का गुनाह है। लेकिन हम रावल के सुझाव पर बात कर रहे हैं। अगर वे रॉय पर ही नाराज थे तो फिर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने ये क्यों कहा कि रॉय की जगह सागरिका घोष को भी लिया जा सकता है?

इसी से मालूम होता है कि यह अरुंधति के खिलाफ सहज क्रोध से अधिक था, इसका मकसद चतुराई से क्रोध का वातावरण पैदा करना था। समाज को क्रोध का इंजेक्शन देना था। यह इसलिए कि यह इस तरह का पहला बयान न था।

अरुंधति रॉय के बारे में रावल ने ये भी कहा कि उनका बर्थ सर्टिफिकेट दरअसल मैटरनिटी वॉर्ड से दिया गया एक माफीनामा है। परेश रावल का मकसद जितना क्रोध व्यक्त करना था, उससे अधिक मानवाधिकार विरोधी वातावरण बनाना था, यह इससे जाहिर हो गया कि उनके बयान का मकसद पूरा हो गया है क्योंकि रावल के बयान के बाद सोशल मीडिया पर ढेर सारे हिंसक सुझाव आए, मसलन एक ने अरुंधति रॉय को अपनी गाड़ी के पीछे घसीटने का इरादा जाहिर किया।

> परेश रावल को खूब मालूम है कि न तो अरुंधति और न सागरिका उन पर मुकदमा दायर करेंगी, हालाँकि जो उन्होंने किया है वह कानूनन जुर्म के दायरे में आ सकता है, हिंसा भड़काने के लिए आइपीसी में धारा 295ए का प्रावधान है, लेकिन बात इससे अधिक गंभीर है। वह यह कि परेश रावल को इसका इत्मीनान है कि इस किस्म का हिंसक और असभ्य बयान देकर भी उनका सभ्य समाज में स्वागत होता ही रहेगा।

लेकिन ऐसे बयान देने वाले लोग प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तक बन चुके हैं। और इन बयानों का मकसद सिर्फ अपनी भड़ास निकालना नहीं, समाज में क्रोध और हिंसा फैलाना है। परेश रावल अभिनेता हैं और भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी। वे सांसद को मिलने वाले विशेषाधिकार के सहारे खुद को सुरक्षित रखते हैं।

अरुंधति रॉय हों या सागारिका घोष या दूसरे मानवाधिकार कार्यकर्ता वे साधारण असुरक्षित नागरिक हैं। उनके खिलाफ भीड़ भड़काई जा सकती है और उसे उन पर हमला करने को उकसाया जा सकता है।

नामुमकिन है कि परेश रावल को यह न मालूम हो कि उन्होंने जो कहा है वो एक तरह की हिंसा को संगठित करना है। मालूम था तभी तो अपने बयान की आलोचना होने पर उन्होंने पूरी ढिठाई साथ कहा कि रॉय क्यों, हमारे पास बड़ी वेरायटी है जिसके साथ यह सलूक किया जा सकता है।

रावल का यह बयान तब आया है जब सोशल मीडिया के जरिए फैलने वाले सन्देश के चलते झारखंड में भीड़ ने सात लोगों को पीट-पीट कर मार डाला है। यानी सोशल मीडिया, जो कि आभासी है, वास्तविक हाड़-मांस वाली खूनी भीड़ पैदा कर सकता है। यही मुज़फ्फरनगर में देखा गया था और यही असम में। इसलिए यह कोई कल्पना नहीं है कि रावल के बयान से अरुंधति रॉय या सागरिका घोष पर हमला हो जाए।

परेश रावल को खूब मालूम है कि न तो अरुंधति और न सागरिका उन पर मुकदमा दायर करेंगी, हालाँकि जो उन्होंने किया है वह कानूनन जुर्म के दायरे में आ सकता है, हिंसा भड़काने के लिए आइपीसी में धारा 295ए का प्रावधान है, लेकिन बात इससे अधिक गंभीर है। वह यह कि परेश रावल को इसका इत्मीनान है कि इस किस्म का हिंसक और असभ्य बयान देकर भी उनका सभ्य समाज में स्वागत होता ही रहेगा।

अधिक चिंता का विषय यह है कि हिंसा और फूहड़पन कब से हमारे लिए सह्य और सभ्य हो गया?

परेश रावल के बयान के पहले कांग्रेस के नेता और पंजाब के मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का लेख छपा जिसमें उन्होंने फारूक डार को जीप के आगे बांधने वाले अफसर को फौज का खास इनाम देने की मांग की।

इतना ही नहीं, उन्होंने लगभग आंख के बदले आंख की नीति की वकालत की। उस लेख में उन्होंने प्रकारांतर से मानवाधिकार कार्यकर्ताओं की खिल्ली भी उड़ाई। भरसक परेश रावल को मालूम है कि उनके समर्थक पुराने संस्कारी महाराजा तक हो सकते हैं।

परेश रावल के ट्वीट के साथ ही फारूक अहमद डार को अपनी गाड़ी के आगे बांधकर गाँव-गाँव घुमाने वाले अफसर को पुरस्कृत किए जाने की खबर भी आई है। इसके मायने यही हैं कि समाज के और राज्य के ताकतवर लोगों ने तय कर लिया है कि शिष्टता, संवैधानिक मूल्य और मानवीय संवेदना अब गुजरे जमाने की बातें हो चुकी हैं।

परेश रावल इसी वजह से ऐसा बयान दे पाए लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि हम इसे भी नजरअंदाज कर दें। जैसे घृणा और हिंसा रोजाना संगठित की जाती हैं और फिर हमारा स्वभाव बन जाती हैं उसी तरह घृणा और हिंसा की हर वारदात या हरकत का विरोध भी किया ही जाना चाहिए। वही सभ्यता को जिंदा रखेगी। *(बीबीसी)*

काँव-काँव

■ बराक और मिशेल ओबामा हनीमून सरीखे घूम रहे हैं...

■■ और ट्रम्प की बीवी उसका हाथ झटक रही है...

चौपाल

अब तो जागो

बिलासपुर में पेड़ों को बचाने हजारों ने जन श्रृंखला बनाकर पेड़ कटाई का विरोध जताया था। सकरी से कोटा (बिलासपुर) तक की सड़क पर इन पेड़ों की घनेरी छांव है। कारों-बड़ी गाड़ियों की रफ्तार में आड़े आने वाले ये पेड़ अब शायद ही बच सकें। एसी गाड़ियों में बैठकर सफर करने वालों को पैदल मुसाफिरों साइकिल वालों की चिंता क्यों होनी चाहिए? इसी बिलासपुर का तापमान दो दिन पहले 49 डिग्री पार कर गया। वास्तव में यह सौ फीसदी सही है कि बिलासपुर के तापमान में अचानक वृद्धि से लोग सांसत में हैं। यह अचानक नहीं हुआ है। दरअसल पांच सात साल पहले तक ही बिलासपुर का तापमान रायपुर से लगभग एक डिग्री सेल्सियस कम हुआ करता था। इस बीच शहर की सीमा पर स्थित सीपत स्थित एनटीपीसी पावर प्लांट के सभी यूनिट चालू हो गए हैं और यहां से 3300 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है। पूर्व के सर्वेक्षण में अनुमान लगा लिया गया था कि इस संयंत्र के कारण बिलासपुर का तापमान दो डिग्री सेल्सियस तक बढ़ जाएगा।

शहर तथा शहर को जोड़ने वाली सड़कों को वाली सड़कों को चौड़ा करने के लिए सैकड़ों की संख्या में पेड़ काटे गए हैं। लिंक रोड को चौड़ा करने के लिए शहर के बीचों बीच 150 हरे-भरे पेड़ों को काटा गया था। नेहरू चौक से महाराणा प्रताप चौक और इस चौक से व्यापार विहार रोड की सड़क चौड़ी करने के लिए भी 160 बड़े-बड़े पेड़ काट दिए गए। इस समय रतनपुर रोड को चौड़ा करने का काम चल रहा है, जिसमें अब तक 1700 पेड़ काटे जा चुके हैं। रायगढ़ रोड को चौड़ा करने के लिए 1400 पेड़ काट लिए गए। इस समय कोटा रोड के चार हजार पेड़ काटने की तैयारी की गई है, जिसका भारी विरोध भी शुरू हो गया है। नगर-निगम ने अधिकांश वार्डों की सड़कें कांक्रीट से बनाई है। गौरव पथ का भी आधा हिस्सा कांक्रीट से बनाया गया है। ये सब शहर के तापमान में लगातार वृद्धि के कारण बन गए हैं। बिलासपुर के लोग जागो, नहीं तो उबलने के लिए तैयार रहो...।

- देवचरण विश्वकर्मा, बिलासपुर

कब बदलेगी मानसिकता

वर्ष 2016 में आपदा, संघर्ष, हिंसा, असुरक्षा और असमानता बढ़ने की वजह से भारत के करीब 28 लाख लोगों को अपना घर/ठिकाना छोड़ना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र संघ की सोमवार 22 मई 2017 को जारी रिपोर्ट के मुताबिक इन प्राकृतिक एवं मानवजनित कारणों के कारण घर छोड़ने के मामले में भारत, चीन और फिलीपींस के बाद दुनिया में तीसरे नंबर पर है. जहां इस 28 लाख में से 4 लाख के विस्थापन का कारण संघर्ष और हिंसा है, वहीं 24 लाख लोगों के विस्थापन की वजह आपदाएं बताई गईं हैं। रिपोर्ट के अनुसार भारत की आर्थिक वृद्धि और सामाजिक सुरक्षा प्रणाली में सुधार के प्रयास, सामाजिक समूहों और लोगों के बीच असमानता को पाटने में विफल रहे हैं। अखबारों और तमाम मीडिया माध्यमों में विकास, प्रगति, संवृद्धि, परिवर्तन और सुधार के बड़े-बड़े दावों की पोल खोलने, चेतने, सबक लेने और सुधरने के लिए यह रिपोर्ट पर्याप्त है, लेकिन क्या हम, हमारी सरकारें, हमारा सरकारी महकमा और हमारे नौकरशाह सुधरने, मानने, सीखने और सबक लेने के लिए तैयार हैं? 21 वीं सदी के लायक हमारी सोच, विचारधारा और मानसिकता कब बनेगी/कब बदलेगी? सामाजिक सरोकारों के समसामयिक, समाजोपयोगी और सार्थक मसलों से भागते हुए सोशल मीडिया पर हमारा भारतीय जनमानस कब तक फोटो, चुटकुला, गपशप, बधाई, जन्मदिन, सालगिरह, बकवाश और बकवाद खेलेगी?

-डॉ. लखन चौधरी

हम वर्ड पॉवर ....

अंग्रेजों ने यदि कम्प्यूटर बनाया है तो, हिन्दुस्तानियों ने शिवलिंग बनाया है। उन्होंने यदि धरती से पेट्रोल-डीजल निकाला है, तो हिन्दुस्तानियों ने धरती से पीरों-महंतों की कब्रें निकाली हैं। उन्होंने यदि जहाज बना कर हवा में उड़ाए, तो हिन्दुस्तानियों ने हाथियों को पूंछ से पकड़ के हवा मे उड़ा दिए, ये अलग बात है कि वो आज तक वापिस नहीं आए। उनकी महिलाएं यदि ओलम्पिक मे खेलतीं हैं, तो हिन्दुस्तानियों की औरतें, साधुओं -तांत्रिकों के पास खेलतीं हैं। जिस चांद पर वो अब पहुंचे हैं, वहां हिन्दुस्तानी माता सदियों से चरखा कात रही है। यदि अंग्रेजों ने सर्च करने के लिए गूगल बनाया है, तो हिन्दुस्तानियों के पास निर्मल बाबा है, जो सब कुछ बता देता है। कैसे बराबरी कर सकते हैं वो हमारे महान देश की, वो आर्थिक तौर पे वर्ड पावर हो सकते हैं, पर पाखंड में हम सदियों से वर्ड पावर हैं।

-अंजु वालेरिया

जातीय हिंसा की जड़ नष्ट हो

बसपा अध्यक्ष मायावती के लौटने के बाद सहारनपुर (उ.प्र.) में फिर हिंसा भड़क उठी। उपद्रवियों के कारण वह प्रदेश जातीय हिंसा के चपेट में आ गया। जाति के मुद्दे को लेकर सामाजिक वातावरण अशांत करना मतलब उसी मुद्दे पर अड़े रहना है। इससे कभी कुछ हासिल नहीं होगा। उससे सिर्फ समाज में जाति के सहारे दीवारें बनती जाएगी और उस कारण किसी छोटे प्रश्न को लेकर भी हंगामा करने का मौका देखा जाएगा। उत्तर प्रदेश में जातिय हिंसा हमेशा सामने आते रहता है। जाति के आधार पर होने वाली लड़ाईयों ने राज्य का वातावरण हमेशा बिगाड़ कर रखा है। जिन्हें समाज में शांति पसंद नहीं ऐसे लोग खासकर के अशांति फैलाने में आगे रहते हैं। खुद का घर सुरक्षित रखकर दूसरों के घर आग में जलते हुए हंसकर देखने वालों को समाज से बाहर किया जाना जरुरी है। क्योंकि वही बदमाश हिंसा की जड़ होते हैं।

-मानसी जोशी

नेत्रदान-देहदान की जरूरत

दान से पुण्य कोई कार्य नहीं होता। दान जहाँ मनुष्य की उदारता का परिचायक है, वहीं यह दूसरों की आजीविका चलाने या किसी सामूहिक कार्य में संकल्पबद्ध होकर अपना योगदान देने की मानवीय प्रवृति को दर्शाता है। बहुत सारे लोग अंधविश्वास के कारण नेत्रदान या देहदान नहीं करते उन्हें यह याद करना चाहिए कि महर्षि दधीचि जैसे ऋषिवर ने तो अपनी अस्थियाँ दान कर दीं। धर्मों की परिभाषा से परे एक मानव धर्म भी है जो सिखाता है कि जिन्दा होकर किसी व्यक्ति के काम आये तो उत्तम है और यदि मृत्यु के बाद भी आप किसी के काम आये तो अतिउत्तम है।

-आकांक्षा, रायपुर

दिल से

When you start to want more than words is when it starts to get complicated.

...and some bridges that you burn, you burn along with them.

देश और दुनिया की इस हफ्ते

■ प्रकाश दुबे

फिरंगी चुनाव, देशी लगाव

एक पखवाड़े की दूरी बची है, ब्रिटेन के चुनाव में। कायदे से भारत सरकार को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। विजय माल्या के प्रत्यर्पण की बेचैनी के बावजूद वित्त मंत्री अरुण जेटली चुनाव पर क्यों ध्यान दें? वित्त, विदेश और गृह मंत्रालय बारीकी से नजरें गड़ाकर बिटिश राजनीतिक दलों के चुनाव घोषणा पत्र बांच रहे हैं। लेबर पार्टी ने सत्ता में आने पर आपरेशन ब्ल्यू स्टार में ब्रिटिश मिलीभगत का सच सामने लाने का चुनावी वादा किया। लंदन में बसे सिखों के एक संगठन का आरोप है कि 1984 में ब्रिटेन ने सैनिक सहायता दी थी। जांच से कांग्रेस और सरदार अमरिंदर सिंह परेशानी में पड़ेंगे। हर मोर्चे पर दुखी जेटली का तो इससे दिलासा मिलेगी।

आपला मार्क्सवादी

भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी-मार्क्सवादी में शीर्ष स्तर पर खींचतान मची है। पश्चिम बंगाल में राज्यसभा में प्रतिनिधि भेजने की गुंजाइश नहीं। केरल से राज्यसभा में प्रतिनिधि जाएगा। माकपा महासचिव सीता राम येचुरी ने केरल के मुख्यमंत्री पिनारायी विजयन की दावेदारी का विरोध किया था। पश्चिम बंगाल में कांग्रेस से चुनावी तालमेल कर केरल के नेताओं की नाराजी बढ़ा दी। नाराज़ विजयन का तर्क है कि केरल के नेताओं को राज्यसभा के लिए माकपा ने तीसरा अवसर नहीं दिया। येचुरी का राज्यसभा में दूसरा कार्यकाल पूरा हो रहा है। विजयन के पास दो मलयाली तुरुप के पत्ते हैं। पूर्व महासचिव प्रकाश कारत मलयाली हैं। उनकी संगिनी वृंदा कारत केरल की बहूरानी हुईं।

साथी हाथ बढ़ाना

चुनाव और चीख-पुकार से पनाह लेने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अमरीका का रुख करेंगे। चुटकुलों की तरह लोकप्रिय अमरीकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प से मिले बगैर परिक्रमा पूरी नहीं होती। विकास प्रेमी प्रधानमंत्री खनिज तेल, ऊर्जा, कोयला क्षेत्र में सहभागिता बढ़ाने पर जोर देंगे। धर्मेन्द्र प्रधान और पीयूष गोयल जैसे युवा समर्थक नींव की ईंट रख आए हैं। प्रधानमंत्री सचिवालय चाहता है कि करार पक्के हों। बर्मा शैल का राष्ट्रीयकरण हुआ था। इंडियन आइल कारपोरेशन समेत सार्वजनिक उपक्रमों ने तैयारी कर ली है। सरकारी कंपनियों के साथ मुकेश अम्बानी की रिलायंस कंपनी भी अमरीकी शैल के साथ भागीदारी में शामिल होगी। सबका साथ, सबका विकास।

चैनल चख चख

जम्मू-कश्मीर में दर्जनों टीवी चैनल प्रतिबंधित कर दिए हैं। केबल आपरेटर बिना अनुमति अनेक चैनल दिखा रहे थे। इनमें पीस टीवी भी है जिसके मुखिया जाकिर को विदेशों से मिलने वाले चंदे की जांच चल रही है। सरकार का आरोप है कि इस चैनल से धार्मिक भावनाएं भड़काने वाली बातें प्रसारित होती थीं। अर्णव गोस्वामी ने रिपब्लिक चैनल आरम्भ किया। टाइम्स नाऊ तो खार खाए बैठा है। खबरिया माल चोरी की शिकायत लेकर अदालत पहुंचा। अर्णव ने जाकिर का इंटरव्यू दिखाया। यह कह कर बिसमिल्लाह किया कि खबरों में अव्वल नंबर हो चुके हैं। बाकी चैनल भी भड़के। नाराज चैनल पूछते हैं कि जहां कम दिखता है, वहां भी नंबर वन?

(लेखक दैनिक भास्कर नागपुर के समूह संपादक हैं)

एलओसी पर इस नई नीति से नुकसान ही दिख रहा है

इंडियन एक्सप्रेस का संपादकीय

मंगलवार को भारतीय सेना ने एक वक्तव्य और वीडियो जारी करके नियंत्रण रेखा के पार पाकिस्तानी बंकरों को तबाह करने की जानकारी दी है। टीवी पर यह वीडियो को देखने वालों ने इस कार्रवाई के कई बड़े मतलब निकाल लिए होंगे, लेकिन अगर सेना का वक्तव्य ध्यान से पढ़ें तो पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है। काफी सावधानी से तैयार किए गए इस वक्तव्य में सिर्फ यह कहा गया है कि पाकिस्तानी चौकियों पर 'आतंकविरोधी और दंडात्मक कार्रवाइयों के तहत समय-समय पर गोलीबारी की जाती है।' यह कोई चौंकाने वाला खुलासा नहीं है। इससे तो यही बात साफ होती है कि नियंत्रण रेखा पर भारत की तरफ से गोलीबारी की जाती रही है।

आतंकवादियों की घुसपैठ रोकने के लिए सेना पहले से गोलीबारी के लिए तैयार थी, और यह कार्रवाई हाल ही में दो भारतीय सैनिकों के सिर काटे जाने के जवाब में नहीं हुई है। गर्मियों में दोनों तरफ से इस तरह की गोलीबारी नियमित रूप से होती रहती है और इसमें कई आम नागरिक और सैनिक मारे जाते हैं। इस दौरान सेना को सीमावर्ती जिलों, राजौरी और पुंछ के कई गांव खाली कराने पड़ते हैं। नियंत्रण रेखा (एलओसी) के उस पार भी ऐसा ही होता है। यह बस बदकिस्मती की बात है कि दोनों देशों के बीच यह परिस्थिति बन गई है। भारत और पाकिस्तान के बीच जो एक अलिखित संघर्ष विराम है वह 2011 के बाद से लगातार कमजोर हुआ है। इसके चलते साल-दर-साल सीमा पर गोलीबारी की घटनाएं तेज होती गई हैं।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कार्यकाल में भारत नियंत्रण रेखा पर तनाव घटाने की परंपरागत नीति से दूर हो चुका है। इसके पीछे यह सोच थी कि अगर भारत सीमा पर सख्त रवैया रखेगा तो गोलीबारी के चलते पाकिस्तानी सेना को हथियारों सहित ढांचागत सुविधाओं का नुकसान होगा और यह कार्रवाई उसे जिहादियों को घुसपैठ में मदद देने से रोकेगी। वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी सेना को उत्तर-पश्चिमी सीमा पर विद्रोही गतिविधियों से भी निपटना पड़ रहा है, सो ऐसे में वह भारत से मुकाबले के लिए पूर्वी सीमा पर और सैनिक व हथियार नहीं भेज पाएगा। हालांकि जमीन पर वैसा कुछ नहीं हुआ जैसा सोचा गया था। यह बात सही है कि पिछले साल लश्कर-ए तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद के पाकिस्तान में मौजूद लॉन्चिंग पैड्स पर भारतीय सेना के हमले के बाद आतंकी हमले नहीं हुए हैं, फिर भी पाकिस्तान में इन संगठनों की गतिविधियां बदस्तूर जारी हैं। वहीं इस बात में भी कोई दोराय नहीं है कि नियंत्रण रेखा पर लड़ाई की कीमत भारत को भी चुकानी पड़ रही है।

भारत को हो रहे नुकसान का एक उदाहरण यही है कि गोलीबारी के चलते कश्मीर सीमा पर बाड़ को सुरक्षित रखने का काम मुश्किल हो गया है, जबकि आतंकियों की घुसपैठ रोकने में इसकी अहम भूमिका है। एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि यह गोलीबारी कश्मीर में पनप रहे विद्रोह को रोकने में कोई काम नहीं दे रही। राजनीतिक कुप्रबंधन के चलते इस विद्रोह को नई ताकत मिल रही है। कुल मिलाकर अब यह बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि पाकिस्तानी चौकियों को तबाह करने की कार्रवाई कोई रणनीति नहीं, बस एक औजार भर है और जिससे कोई मकसद हासिल नहीं हो रहा है। *(सत्याग्रह)*

एक ग़ज़ल गुनगुनाएं

आप ने क़द्र कुछ न की दिल की
उड़ गई मुफ़्त में हँसी दिल की

ख़ू है अज़-बस कि आशिक़ी दिल की
ग़म से वाबस्ता है ख़ुशी दिल की

याद हर हाल में रहे वो मुझे
अल-ग़रज़ बात रह गई दिल की

मिल चुकी हम को उन से दाद-ए-वफ़ा
जो नहीं जानते लगी दिल की

चैन से महव-ए-ख़्वाब-ए-नाज़ में वो
बेकली हम ने देख ली दिल की

हमा-तन सर्फ़-होश्यारी-ए-इश्क़
कुछ अजब शय है बे-ख़ुदी दिल की

उनसे कुछ तो मिला वो ग़म ही सही
आबरू कुछ तो रह गई दिल की

मर मिटे हम न हो सकी पूरी
आरज़ू तुम से एक भी दिल की

वो जो बिगड़े रक़ीब से *हसरत*
और भी बात बन गई दिल की।

-हसरत मोहानी

I CAN CHOOSE TO LET IT DEFINE ME, CONFINE ME, REFINE ME, OUTSHINE ME, OR I CAN CHOOSE TO MOVE ON AND LEAVE IT BEHIND ME.